



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025

Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

## विकसित भारत @2047: समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में बहु-विषयक एवं बहु-संस्थागत प्रयास

**Dr. Ritu Kumari**

Assistant Professor, Department of Economic, R.M.W. College Nawada, MU Bodh Gaya

Email: rituvcnwd123@gmail.com

### भूमिका

भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की परिकल्पना की गई है। यह सपना केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास, तकनीकी उन्नति, सामाजिक न्याय, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, उद्योग, कृषि, और हरित ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति आवश्यक होगी। इस संदर्भ में, बहु-विषयक एवं बहु-संस्थागत प्रयासों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी की भागीदारी अनिवार्य होगी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सबसे पहले भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था। राजीव गांधी, जो 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके आर्थिक विचार और नीतियों ने भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यहां उनकी आर्थिक सोच और योगदान के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

### 1. तकनीकी और विज्ञान का महत्व

राजीव गांधी ने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तकनीकी उन्नति और विज्ञान का विकास जरूरी है। उन्होंने कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया, जिसने आगे चलकर भारत को "IT सुपरपावर" बनाने में मदद की।

### 2. उदारीकरण की नींव

राजीव गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। उन्होंने लाइसेंस राज को कम करने और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की नीतियों को लागू किया। हालांकि पूर्ण उदारीकरण 1991 में हुआ, लेकिन राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी।

### 3. शिक्षा और मानव संसाधन विकास

राजीव गांधी ने शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति (1986) लागू की, जिसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। उनका मानना था कि शिक्षित और कुशल युवा ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

#### 4. ग्रामीण विकास और पंचायती राज

राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

#### 5. उद्योग और निर्यात को बढ़ावा

राजीव गांधी ने उद्योगों के विकास और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां बनाईं। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को समर्थन दिया और निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए।

#### 6. युवाओं पर विश्वास

राजीव गांधी ने युवाओं को देश के विकास का मुख्य आधार माना। उन्होंने युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकती है।

#### 7. संचार और परिवहन का विकास

राजीव गांधी ने संचार और परिवहन के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उन्होंने दूरसंचार और रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिली।

- तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। इस महत्कंशी कांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने “**राष्ट्रीय गति शक्ति योजना**” को लागू किया।
- राष्ट्रीय गति शक्ति योजना (National Gati Shakti Plan) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे (infrastructure) को मजबूत करना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। यह योजना विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके बुनियादी ढांचे के विकास को तेज और प्रभावी बनाने पर केंद्रित है।

#### राष्ट्रीय गति शक्ति योजना के मुख्य उद्देश्य:

- बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास: इस योजना का लक्ष्य सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जलमार्ग, और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में समन्वित विकास करना है।
- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय: यह योजना विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लागत को कम करने का प्रयास करती है।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए यह योजना परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने पर जोर देती है।
- रोजगार सृजन: बुनियादी ढांचे के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- डिजिटल मैपिंग और प्लानिंग: इस योजना में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की योजना और निगरानी की जाएगी।

#### राष्ट्रीय गति शक्ति योजना के प्रमुख घटक:

1. सड़क और राजमार्ग: देश भर में सड़क नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन।
2. रेलवे: रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और नए रेल मार्गों का निर्माण।
3. हवाई अड्डे: हवाई अड्डों का विस्तार और उन्नयन, विशेषकर छोटे शहरों में।
4. बंदरगाह: बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का निर्माण।
5. जलमार्ग: नदियों और नहरों का उपयोग करके जलमार्गों का विकास।
6. लॉजिस्टिक्स पार्क: लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण करके आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।
7. ऊर्जा और गैस पाइपलाइन: ऊर्जा और गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार।

#### राष्ट्रीय गति शक्ति योजना के लाभ:

- आर्थिक विकास: बुनियादी ढांचे के विकास से देश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी।
- रोजगार के अवसर: निर्माण और रखरखाव के क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा होंगी।
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से व्यवसायों को फायदा होगा।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: बेहतर बुनियादी ढांचे से भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति में आएगा।
- किसानों और उद्योगों को लाभ: बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक्स से किसानों और उद्योगों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी।

राष्ट्रीय गति शक्ति योजना भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित विकास को बढ़ावा देकर देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी। हालांकि, इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होगा और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।

#### अमृतकाल के दौरान जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को भुनाने की रणनीति

भारत अमृतकाल (2022-2047) में प्रवेश कर चुका है, जो इसे एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस अवधि में देश की युवा जनसंख्या (Demographic Dividend) को सही दिशा में प्रशिक्षित एवं उत्पादक बनाने से भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसे भुनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025

Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

#### 1. शिक्षा एवं कौशल विकास

- ✓ नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का प्रभावी क्रियान्वयन – व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- ✓ कौशल विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहल को मजबूत करना।
- ✓ इंडस्ट्री-अकादमिक साझेदारी – विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाना।

#### 2. रोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन

- ✓ MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा – नवाचार (Innovation) और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
- ✓ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन – विनिर्माण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना।
- ✓ ग्रीन और डिजिटल जॉब्स – सतत विकास और तकनीकी क्रांति से जुड़े रोजगार अवसरों का निर्माण।

#### 3. स्वास्थ्य एवं पोषण

- ✓ स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) जैसी योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू करना।
- ✓ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार – कुपोषण और बाल मृत्यु दर को कम करना।
- ✓ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान – युवाओं में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान।

#### 4. डिजिटल क्रांति एवं नवाचार

- ✓ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
- ✓ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और डेटा साइंस – युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना।
- ✓ ई-गवर्नेंस और डिजिटल बैंकिंग – सरकारी सेवाओं और डिजिटल लेन-देन को सुगम बनाना।

#### 5. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

- ✓ महिला सशक्तिकरण – आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को सक्षम बनाना।
- ✓ कार्यस्थल पर लैंगिक समानता – महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं में प्रोत्साहित करना।
- ✓ महिला उद्यमिता को समर्थन – महिला स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सहयोग देना।

#### 6. शहरीकरण एवं बुनियादी ढांचे का विकास

- ✓ स्मार्ट सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर – बेहतर आवास, परिवहन और कनेक्टिविटी।
- ✓ ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर – सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास पर जोर।
- ✓ सुलभ और किफायती आवास योजनाएँ – शहरी श्रमिकों और युवाओं के लिए बेहतर जीवन स्तर।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025

Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

## 7. कृषि एवं ग्रामीण विकास

- ✓ स्मार्ट एग्रीकल्चर – कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग बढ़ाना।
- ✓ एफपीओ (FPO) और कोऑपरेटिव मॉडल – किसानों को बाजार से सीधे जोड़ना।
- ✓ ग्राम उद्यमिता को बढ़ावा – ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।

भारत यदि अपनी युवा जनसंख्या को उचित शिक्षा, कौशल और अवसर प्रदान करता है, तो अमृतकाल में यह जनसांख्यिकीय लाभांश भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना सकता है। सरकार, उद्योगों और समाज को मिलकर इन रणनीतियों पर कार्य करना होगा ताकि युवा भारत की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

**"युवा शक्ति, आत्मनिर्भर भारत की कुंजी!"**

### आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक सशक्त और समावेशी आर्थिक ढांचे की आवश्यकता है। यह केवल उच्च जीडीपी विकास दर प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी वर्गों और क्षेत्रों को समान रूप से लाभान्वित करने वाला होना चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

#### ➤ विनिर्माण और उद्योग:

‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने और उच्च गुणवत्ता वाली निर्यातानुमुखी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, उद्योग 4.0 तकनीकों जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को भारतीय उद्योगों में अपनाने से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल की जा सकती है। स्थायी औद्योगीकरण के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सके।

#### ➤ कृषि और ग्रामीण विकास:

स्मार्ट कृषि तकनीकों और जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। इसके लिए ड्रोन, सटीक खेती (Precision Farming), और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी नवीनतम तकनीकों को अपनाना अनिवार्य होगा। किसानों को जलवायु-अनुकूल फसलों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, और कार्बन-तटस्थ खेती की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार, और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें बाजार तक सीधी पहुँच प्रदान करना आवश्यक होगा।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

#### भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि: 44 से 61 मिलियन मीट्रिक टन तक का सफर:

भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। दुग्ध उत्पादन न केवल पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह लाखों किसानों के लिए आजीविका का साधन भी है। यदि भारत में अगले आठ वर्षों में दुग्ध उत्पादन को 44 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 61 मिलियन मीट्रिक टन किया जाए, तो इससे रोजगार, किसानों की आय और डेयरी सहकारी समितियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक, सरकारी नीतियों, पशुपालन में सुधार, बेहतर विपणन रणनीतियों और सहकारी समितियों के विस्तार की आवश्यकता होगी।

#### दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का महत्व

भारत में दूध का उत्पादन केवल उपभोग के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत भी है। यदि दुग्ध उत्पादन को 44 मिलियन मीट्रिक टन से 61 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाए, तो इसके अनेक लाभ होंगे:

1. **किसानों की आय में वृद्धि:** दूध उत्पादन में वृद्धि से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
2. **रोजगार सृजन:** डेयरी उद्योग में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को आजीविका का बेहतर साधन मिलेगा।
3. **सहकारी समितियों का विस्तार:** अधिक उत्पादन से अधिक किसानों को संगठित करने की आवश्यकता होगी, जिससे डेयरी सहकारी समितियों की संख्या बढ़ेगी।
4. **पोषण सुरक्षा:** दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ने से पोषण स्तर में सुधार होगा और कुपोषण की समस्या कम होगी।
5. **निर्यात क्षमता में वृद्धि:** अधिक उत्पादन से भारत दुग्ध उत्पादों का निर्यात कर सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

#### उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम

1. उन्नत पशुपालन तकनीक अपनाना

दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत पशुपालन तकनीकों को अपनाना आवश्यक होगा। इसमें शामिल हैं:

- ✓ उच्च दुग्ध उत्पादक नस्लों का प्रजनन
- ✓ पशु आहार और पोषण प्रबंधन में सुधार
- ✓ स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक अपनाना
- ✓ आधुनिक डेयरी फार्मिंग उपकरणों का उपयोग



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक पशुपालन के तरीकों की जानकारी देनी होगी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े।

#### 2. पशुओं के स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान देना

स्वस्थ गाय और भैंस ही अधिक दूध दे सकती हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- ✓ नियमित टीकाकरण और बीमारियों की रोकथाम
- ✓ पशुओं के रहने के लिए स्वच्छ और अनुकूल वातावरण प्रदान करना
- ✓ पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना
- ✓ सरकारी स्तर पर मुफ्त पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना

यदि पशु स्वस्थ रहेंगे, तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

#### 3. आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन

दूध उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ उसे सही तरीके से बाजार तक पहुँचाना भी आवश्यक है। इसके लिए:

- ✓ आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना
- ✓ कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं में सुधार
- ✓ ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग
- ✓ डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग और निर्यात बढ़ाना

यदि किसान अपने उत्पादों को सही कीमत पर बेच पाएंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

#### 4. डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार

डेयरी सहकारी समितियाँ किसानों को संगठित करने और उन्हें बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए:

- ✓ छोटे और सीमांत किसानों को डेयरी सहकारी समितियों से जोड़ना
- ✓ सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देना
- ✓ आधुनिक दुग्ध संग्रहण और वितरण प्रणाली लागू करना
- ✓ सहकारी समितियों को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना

गुजरात का अमूल मॉडल एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सहकारी समितियाँ दुग्ध उत्पादन में क्रांति ला सकती हैं। इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

#### 5. सरकारी नीतियाँ और वित्तीय सहायता

सरकार को किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उचित नीतियाँ बनानी होंगी, जैसे कि:

- ✓ डेयरी उद्योग के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता
- ✓ किसानों को सस्ते दर पर पशु चारा और दवाएँ उपलब्ध कराना
- ✓ डेयरी क्षेत्र में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना
- ✓ पशुपालन के लिए आसान ऋण और बीमा योजनाएँ शुरू करना

सरकार के सहयोग से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे।

#### उत्पादन बढ़ने से होने वाले आर्थिक और सामाजिक लाभ

##### 1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार

दुग्ध उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी, जिससे समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

##### 2. महिला सशक्तिकरण

भारत में डेयरी उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है। यदि दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, तो अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

##### 3. नई नौकरियों का सृजन

डेयरी क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी।

##### 4. निर्यात में वृद्धि

अधिक दुग्ध उत्पादन होने से भारत वैश्विक बाजार में अपने डेयरी उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ेगी।

यदि भारत अगले आठ वर्षों में दुग्ध उत्पादन को 44 मिलियन मीट्रिक टन से 61 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। यह लक्ष्य पशुपालन में सुधार, सहकारी समितियों के विस्तार, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और सरकारी सहयोग से संभव हो सकता है।

डेयरी उद्योग में सुधार से न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत पहले ही वैश्विक दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, और यदि यह रणनीति सही तरीके से अपनाई जाए, तो देश आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर सकता है।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

#### डिजिटल अर्थव्यवस्था:

भारत की आईटी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना अनिवार्य होगा। भारत को 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाकर डिजिटल परिवर्तन को गति देनी होगी। डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर नागरिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए।

#### डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक:

- **ई-कॉमर्स:** ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मित्रा डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- **डिजिटल भुगतान:** यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान सरल और तेज़ हो गया है।
- **डिजिटल सेवाएँ:** क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म (जैसे BYJU'S, Unacademy) ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है।
- **रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग:** इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में लोग वर्क-फ्रॉम-होम और फ्रीलांसिंग के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं।

#### डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ:

- ✓ तेज़ और सुरक्षित लेन-देन
- ✓ नौकरी और उद्यमिता के नए अवसर
- ✓ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक आसान पहुंच
- ✓ पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी
- **नवाचार एवं अनुसंधान:** वैज्ञानिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और रिसर्च हब स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए उन्नत प्रयोगशालाओं, सरकारी एवं निजी अनुसंधान अनुदानों, और विश्वविद्यालयों में शोध को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, और नैनो तकनीक जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता परिवेश को और अधिक सशक्त बनाना होगा।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

## समावेशी विकास और सामाजिक प्रगति

एक विकसित भारत के लिए सामाजिक समावेश आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि समाज के सभी वर्गों को आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से समान अवसर मिलने चाहिए। केवल आर्थिक वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच, सामाजिक न्याय, रोजगार अवसरों में समानता, और गरीब एवं वंचित वर्गों को सशक्त बनाने जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।

सामाजिक प्रगति का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देने से है। यह सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण संतुलन को भी समाहित करता है। यदि समाज के किसी भी वर्ग को विकास की धारा से बाहर रखा जाता है, तो यह समावेशी विकास की संकल्पना के विपरीत होता है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समावेशी विकास और सामाजिक प्रगति के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे कि **प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, और आयुष्मान भारत**। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाना है।

समावेशी विकास और सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाए। प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराकर ही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और न्यायसंगत समाज की स्थापना की जा सकती है।

## वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत:

भारत को 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए व्यापक रणनीतिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। इसे प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी कूटनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षमताओं को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। विशेष रूप से, भारत को वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी निभाने और विकासशील तथा विकसित देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना होगा।

## आर्थिक सशक्तिकरण

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकों के विकास ने भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

### वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी

भारत की विदेश नीति संतुलित और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, और अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत की मजबूत कूटनीतिक साझेदारियाँ हैं। क्वाड (QUAD), ब्रिक्स (BRICS) और G20 जैसे वैश्विक संगठनों में भारत की सक्रिय भूमिका उसकी बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति को दर्शाती है।

### वैज्ञानिक और तकनीकी विकास

भारत ने अंतरिक्ष और तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। चंद्रयान, मंगलयान और हाल ही में चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाया है।

### सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव

योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम्' की नीति विश्व को एकजुट करने की दिशा में सहायक है।

### सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण :

पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना आवश्यक है।

### नीतिगत दृष्टिकोण :

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुआयामी नीति निर्माण आवश्यक होगा। यह केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक समावेश, वैज्ञानिक उन्नति और पर्यावरणीय संतुलन को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। इसके तहत निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा:

#### ➤ साक्षरता और शिक्षा सुधार:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली विकसित कर युवाओं को नवाचार, शोध और व्यावहारिक कौशल के लिए प्रेरित करना, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बन सकें। डिजिटल शिक्षा, बहु-विषयक शिक्षण प्रणाली, और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक होगा, जिससे भारत ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन सके।

#### ➤ बुनियादी ढांचे का विकास:

आधुनिक परिवहन, ऊर्जा संसाधन, और शहरी नियोजन को बढ़ावा देना। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विस्तार से देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। स्मार्ट सिटी



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

परियोजनाओं को बढ़ावा देकर शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा, ताकि गांवों में भी समान विकास सुनिश्चित किया जा सके।

#### ➤ तकनीकी क्रांति:

डिजिटल इंडिया पहल को और मजबूत बनाकर भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनाना। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। साथ ही, डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइस तक पहुंच बढ़ानी होगी। तकनीकी स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को सहयोग देकर भारत को आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी क्रांति ने उद्योगों को भी पूरी तरह से बदल दिया है। ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग की वजह से उत्पादन की गुणवत्ता और गति में सुधार हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यह क्रांति जीवनरक्षक सिद्ध हो रही है। नई चिकित्सा तकनीकों के कारण जटिल बीमारियों का इलाज संभव हो सका है। शिक्षा प्रणाली भी डिजिटल प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।

हालांकि, तकनीकी क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। बेरोजगारी बढ़ने, डेटा गोपनीयता की समस्याएँ और साइबर अपराध जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं। लेकिन अगर तकनीकी विकास को सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो यह मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित हो सकता है।

संक्षेप में, तकनीकी क्रांति ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और यह आगे भी नई संभावनाओं के द्वार खोलती रहेगी।

#### ➤ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:

सबके लिए किफायती और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करना, आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपनाना, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना, तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल है। साथ ही, सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें।

#### ➤ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण:

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर भारत को कार्बन-न्यूट्रल राष्ट्र बनाना। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, जलवायु अनुकूलन नीतियों को लागू करना और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करना आवश्यक होगा। वृक्षारोपण अभियानों, जल संरक्षण उपायों, तथा सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना होगा। उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

करने के लिए कड़े नियम लागू करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विस्तार भी किया जाना चाहिए।

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर COP28 (Conference of the Parties) सम्मेलन दिसंबर 2023 में **दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत आयोजित किया जाता है, और इस बार इसकी मेजबानी UAE ने की।

#### COP28 के मुख्य बिंदु:

##### 1. जीवाश्म ईंधन पर चर्चा:

COP28 में जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस) के उपयोग को कम करने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर दिया गया। कई देशों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन कुछ देशों ने इसका विरोध किया।

##### 2. नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार:

सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जल विद्युत) के उपयोग को बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने पर सहमति बनी।

##### 3. जलवायु वित्त:

विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर चर्चा हुई। धनी देशों से ग्रीन क्लाइमेट फंड को मजबूत करने का आग्रह किया गया।

##### 4. लॉस एंड डैमेज फंड:

COP28 में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और विनाश (Loss and Damage) के लिए एक फंड बनाने पर सहमति हुई। यह फंड विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से निपटने में मदद करेगा।

##### 5. ग्लोबल स्टॉकटेक:

पेरिस समझौते (2015) के लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake) प्रक्रिया पूरी हुई। इसमें पाया गया कि दुनिया अभी भी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने के लक्ष्य से पीछे है।

##### 6. युवाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी:

सम्मेलन में युवाओं और स्थानीय समुदायों को जलवायु कार्रवाई में शामिल करने पर जोर दिया गया।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

#### समझौते और चुनौतियाँ:

- COP28 में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेकिन जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने और जलवायु वित्त के मुद्दे पर कुछ मतभेद बने रहे।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारी और वित्तीय सहायता को लेकर तनाव बना हुआ है।

वर्ष 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि पुर्नस्थापन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर ध्यान केन्द्रित करना था। जिसका नारा था “हमारी भूमि हमारा भविष्य”।

वर्तमान में, दुनिया की 40% भूमि बंजर हो चुकी है, जिसका असर मरुस्थलीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 3.2 बिलियन लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा, अनुमानों से पता चलता है कि 2050 तक दुनिया की तीन-चौथाई से ज़्यादा आबादी सूखे से प्रभावित होगी। इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) COP16 से पहले मनाया जा रहा है, जो दिसंबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को भूमि और सूखे पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन माना जा रहा है।

मानव द्वारा प्रेरित पर्यावरणीय क्षति बढ़ती जा रही है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान और भूमि का रेगिस्तानीकरण। वर्तमान पीढ़ी के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और भूमि और प्रकृति को उनकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाएँ।

#### निष्कर्ष

भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर बहु-विषयक और बहु-संस्थागत प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए सरकार, उद्योग, शिक्षा संस्थानों और नागरिक समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, समावेशी विकास और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के क्षेत्रों में निरंतर सुधार से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, भारत को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनानी होंगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक संतुलन बना रहे। नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सशक्त करने के लिए कूटनीतिक रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को भी मजबूत करना आवश्यक होगा।

भारत को संयुक्त राष्ट्र (UN), G20, BRICS, QUAD, SCO और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में अपनी भूमिका को और मजबूत करना होगा। विशेष रूप से UNSC में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास जारी रखने होंगे।



### International Conference – 2025: Developed India @ 2047

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

#### रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियाँ

- ✓ अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ASEAN देशों के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना होगा।
- ✓ भारत को "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" अभियानों के तहत वैश्विक कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना चाहिए।

#### पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध

- ✓ "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के तहत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना होगा।
- ✓ चीन के साथ संतुलित कूटनीति अपनाते हुए व्यापार और सामरिक हितों की रक्षा करनी होगी।

#### हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी भूमिका

- ✓ QUAD (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए।
- ✓ इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत ASEAN और अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा।

#### रक्षा और तकनीकी सहयोग

- ✓ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों के साथ रक्षा साझेदारियों को और मजबूत करना होगा।
- ✓ साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत टेक्नोलॉजी में वैश्विक सहयोग विकसित करना चाहिए।

#### वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्वकारी भूमिका

- ✓ जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा (ISA - International Solar Alliance) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।
- ✓ विकासशील देशों की आवाज़ बनकर भारत को उनके हितों की रक्षा करनी होगी।

#### सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी

- ✓ योग, आयुर्वेद, भारतीय सिनेमा और साहित्य के माध्यम से सॉफ्ट पावर को और मजबूत करना चाहिए।
- ✓ प्रवासी भारतीयों को भारत की विदेश नीति में अधिक प्रभावी भूमिका देने की जरूरत है।

अगर भारत इन रणनीतियों को प्रभावी रूप से अपनाता है, तो वह निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है।

\*\*\*\*\*

**International Conference – 2025: Developed India @ 2047**

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

Here are Some Book References That Align with The Themes Discussed in My Article on "Viksit Bharat @2047":

**Economic Development & Self-Reliance**

1. **"India Unbound"** – Gurcharan Das
  - Discusses India's economic transformation and its journey towards becoming a developed nation.
2. **"The Rise of India: Its Transformation from Poverty to Prosperity"** – Niranjan Rajadhyaksha
  - Examines India's economic growth and the reforms needed for sustained development.
3. **"Ignited Minds"** – Dr. A.P.J. Abdul Kalam
  - Talks about India's potential to become a developed nation through innovation, education, and self-reliance.

**Social Inclusion & Sustainable Development**

4. **"Why Nations Fail"** – Daron Acemoglu & James A. Robinson
  - Explores how inclusive institutions drive development and how India can strengthen its democratic and economic institutions.
5. **"The India Way: Strategies for an Uncertain World"** – S. Jaishankar
  - Discusses India's role in global affairs, diplomacy, and international leadership.
6. **"Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty"** – Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo
  - Provides insights into poverty alleviation strategies relevant to India's inclusive growth vision.

**Innovation, Technology & Infrastructure**

7. **"The Fourth Industrial Revolution"** – Klaus Schwab
  - Discusses emerging technologies like AI, blockchain, and IoT, which are crucial for India's future development.
8. **"Digital India: Understanding Information, Communication and Social Change"** – Pradip Ninan Thomas
  - Examines India's digital transformation and how it can lead to a developed nation.
9. **"Mission India"** – Dr. A.P.J. Abdul Kalam & Y.S. Rajan
  - Outlines a roadmap for India's technological and economic progress by 2020, which remains relevant for 2047.



**International Conference – 2025: Developed India @ 2047**

**Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025**

**Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi**

**Environment & Climate Change**

10. **"The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable"** – Amitav Ghosh
  - Discusses climate change challenges relevant to India's environmental policies.
11. **"An Uncertain Glory: India and Its Contradictions"** – Jean Drèze & Amartya Sen
  - Analyzes India's economic progress and sustainability challenges.
12. **"Our Future Earth: A New Framework for Sustainability"** – Curt Stager
  - Discusses sustainable development practices that India can adopt.

These books provide deep insights into India's journey towards becoming a developed nation by 2047.